राष्ट्रीय हितों के संवर्धन में बदलते हैं दोस्त और दुश्मन

डॉ.ब्रह्मदीप अलूने
(अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)

अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वास्तविकता यह है की यहां न तो कोई स्थाई दोस्त होता है,न स्थाई दुश्मन होता है और न ही कोई स्थाई गठबंधन होता है. राष्ट्रीय हितों के संवर्धन के लिए समय,परिस्थिति और रणनीतिक लाभ के अनुसार दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं. तेल की दुनिया के दो मजबूत साथी माने जाने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते अब अलग अलग हो गए है. सऊदी अरब नियन्त्रण और संतुलन की यथार्थता को स्वीकार करके पाकिस्तान के प्रभाव में चीन की ओर जाने को तैयार है,वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक से अलग होने की घोषणा कर रणनीतिक स्वायत्ता को संदेश दे दिया है. दरअसल तेल की दुनिया में मजबूत हैसियत रखने वाले संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक से अलग होने का निर्णय आर्थिक साधनों का रणनीतिक उपयोग बेहतर तरीके से कर भू-राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कोशिश नजर आता है.

मध्यपूर्व की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था संयुक्त अरब अमीरात को वी द यूएई 2031 योजना के तहत,देश का लक्ष्य सतत विकास और एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है. वह मध्यपूर्व की धार्मिक और सामरिक प्रतिद्वंदिता का शिकंजे से बाहर निकलकर तथा तेल पर निर्भरता कम करके पर्यटन,एआई और एयरोस्पेस पर आधारित विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. भू-अर्थशास्त्र आज की विश्व व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है. विभिन्न देश अब व्यापार,निवेश और तकनीक के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ा रहे है,जिससे वैश्विक राजनीति का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. भौगोलिक रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित यूएई एक प्रमुख वैश्विक व्यापारिक केंद्र है. 2015 से भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और अब ओपेक से अलग रुख उसके बढ़ती भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है.

ईरान और अमेरिका युद्द में संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के कई हमलों को झेला है और वह ईरान समेत सऊदी अरब जैसे देशों से नाराज है. ऐसी परिस्थितियों में यूएई के आगामी कदम मध्यपूर्व की राजनीति पर गहरे असर डाल सकते है. यूएई के अमेरिका,इजराइल और

भारत से मजबूत सम्बन्ध है और मध्यपूर्व की बदलती परिस्थितियों में इसका व्यापक रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. दुनिया के धनी देशों में शुमार यूएई की पूंजी, इज़राइल की तकनीक,भारत का बाजार और अमेरिका का समर्थन,मध्यपूर्व के नये आर्थिक-रणनीतिक समूह के रूप में गेमचेंजर साबित हो सकते है. इसकी संभावना इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इन देशों ने सहयोग का खाका पहले ही तैयार कर लिया था. गौरतलब है की आई2यू2 2021 में स्थापित भारत, इज़राइल,संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का एक रणनीतिक और आर्थिक गठबंधन है,इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, जल, ऊर्जा, परिवहन,अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है. यूएई के ओपेक से बाहर होते ही के मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ गई है. यह समूह आपसी व्यापार,साझा सुरक्षा और कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए एक साथ आगे बढ़ सकता है. ईरान से युद्द में सऊदी अरब के रुख से ट्रम्प ने अपनी नाराजगी कई बार सार्वजनिक रूप से जाहिर की है और इससे अमेरिका के इस मजबूत सहयोगी से संबंधों पर असर पड़ना तय है.

युद्द के बीच सऊदी अरब में पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों का जाना,अमेरिका पर से सऊदी अरब की सैन्य निर्भरता कम करने की कोशिश ज्यादा नजर आई. मध्यपूर्व में अमेरिका के रणनीतिक हित सऊदी अरब,पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य गठबंधन से प्रभावित हो सकते है,ट्रम्प इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकते है. वहीं संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व में एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है. यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक स्थान पर स्थित है,जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक प्रमुख व्यापारिक हब के रूप में काम करता है. अमेरिका के लिए यह देश बहुत महत्वपूर्ण है और ओपेक से अलग होकर यूएई ने अमेरिका को मजबूत ही किया है. इससे अमेरिका की शैल नीति या शैल क्रांति को व्यापक मजबूती मिल सकती है. शैल क्रांति,अमेरिका में 2000 के दशक की शुरुआत आई एक तकनीकी क्रांति है,जिसने अमेरिका की ऊर्जा व्यवस्था को मूल रूप से बदलते हुए उसे वैश्विक शक्ति संतुलन में नई ऊँचाई पर पहुंचा दिया. हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और क्षैतिज ड्रिलिंग जैसी तकनीकों के माध्यम से अमेरिका ने चट्टानों में फंसे तेल और गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया. इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका,जो कभी पश्चिम एशिया पर ऊर्जा के लिए निर्भर था,वह स्वयं एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक बन गया.

ऊर्जा आत्मनिर्भरता ने अमेरिका की विदेश नीति को अधिक स्वतंत्र बनाया. अब उसे मध्य पूर्व के तेल पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं रही,जिससे वह वहां के जटिल संघर्षों में सीमित हस्तक्षेप की नीति अपना सका. इसके साथ ही,वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका की बढ़ती उपस्थिति ने उसे आर्थिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर लाभ पहुंचाया. ऊर्जा निर्यात के माध्यम से उसने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया,बल्कि यूरोप और एशिया के देशों पर भी प्रभाव बढ़ाया. इस क्रांति का सबसे बड़ा असर सऊदी अरब और अन्य ओपेक देशों पर पड़ा. पहले जहां ओपेक के माध्यम से सऊदी अरब तेल की कीमतों और आपूर्ति को नियंत्रित करता था,वहीं अमेरिकी शेल उत्पादन ने इस नियंत्रण को कमजोर कर दिया. वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सऊदी की बाजार हिस्सेदारी घटी और कीमतों पर उसका प्रभाव सीमित हो गया. 2014-15 में सऊदी अरब ने उत्पादन बढ़ाकर कीमतें गिराने की रणनीति अपनाई,जिससे अमेरिकी शेल कंपनियां बाजार से बाहर हो जाएं. लेकिन इसके विपरीत,अमेरिकी कंपनियों ने अपनी तकनीक और लागत दक्षता में सुधार कर लिया,जिससे वे और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गईं. परिणामस्वरूप,सऊदी अरब को आर्थिक दबाव और राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ा. इस प्रकार शेल क्रांति ने अमेरिका को ऊर्जा महाशक्ति बना दिया,जबकि सऊदी अरब के पारंपरिक वर्चस्व को चुनौती मिली,जिससे वैश्विक भू-राजनीति में शक्ति संतुलन का पुनर्निर्माण हुआ.

वहीं यूएई अमेरिका और सऊदी अरब की प्रतिद्वंदिता से अलग होकर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ा और अब वह ओपेक से अलग होकर अमेरिका का तकनीकी फायदा लेना चाहता है. यूएई यह बखूबी जानता है की इज़राइल के साथ सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से वह मुस्लिम दुनिया को नाराज कर सकता है,जिसका जोखिम वह लेना नहीं चाहता. लेकिन इजराइल से उसने संबंधों को मजबूत किया है,जिससे इजराइल की तकनीक का फायदा उठाया जा सके. इज़राइल तकनीकी नवाचार का केंद्र है,सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद उसने कृषि,जल प्रबंधन,साइबर सुरक्षा और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है. ड्रिप इरिगेशन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक,उसकी तकनीकें वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है. यूएई-इजराइल संबंध आधुनिक पश्चिम एशियाई राजनीति में नए गठबंधनों और बदलते हितों का प्रतीक है. अमेरिका के हितों का ध्यान रखते हुए यूएई ने इजराइल के साथ आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए है और यह स्थिति ट्रम्प की मंशा के अनुरूप है.

यूएई के लिए भारत बेहद महत्वपूर्ण देश है जबकि संयुक्त अरब अमीरात भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम देश है. भारत से यूरोप तक बनने वाले नए आर्थिक गलियारे में यूएई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. यह कॉरिडोर,जिसे भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा कहा जाता है,वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नया स्वरूप देने की क्षमता रखता है. यह भारत को यूएई,सऊदी अरब,जॉर्डन,इजराइल और यूरोप से समुद्री और रेल मार्ग द्वारा जोड़कर व्यापार को आसान,तेज और सस्ता बनाने की पहल है,जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका की चीन के प्रभाव को कम करने के लिए इस परियोजना में गहरी दिलचस्पी है. यूएई की कुल आबादी नब्बे लाख है और इसमें दो तिहाई प्रवासी है. इन प्रवासियों में करीब छब्बीस लाख भारतीय है,यह कुल आबादी लगभग का तीस फ़ीसदी है और यह प्रवासियों का सबसे बड़ा हिस्सा है. यूएई दुनिया का दूसरा देश है,जहां भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात है. दुबई भारत के लिए व्यापार,यात्रा और आपूर्ति प्रबंधन का हब है,हर साल लाखों लोग यहां से आवाजाही करते है. दुबई जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा भारतीय होते है और यहां स्थित कंपनी डीपी वर्ल्ड और एमार का भारत में बड़ा निवेश है तो दूसरी तरफ़ भारतीय कंपनियों ने भी दुबई को अपना केंद्र बना रखा है.

> सऊदी अरब ने अपनी विजन-2030 योजना के तहत अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रयास तेज किए है तथा अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर रियाद में क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने का दबाव भी डाला है. सऊदी अरब लंबे समय से धार्मिक और तेल शक्ति के कारण मध्य पूर्व का प्रमुख नेता रहा है. वहीं यूएई एक आधुनिक,तकनीक-आधारित और वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उभर रहा है. उसकी खुली अर्थव्यवस्था और तेज निर्णय क्षमता उसे एक वैकल्पिक नेतृत्व मॉडल प्रदान करती है,जो पारंपरिक सऊदी मॉडल को चुनौती देता है. पाकिस्तान के सैन्य गठबंधन में शामिल होकर सऊदी अरब ने भारत,इजराइल और यूएई के लिए जो रणनीतिक चुनौती बढाई थी,यूएई ने ओपेक से अलग होकर मध्यपूर्व ,तेल के भू-अर्थशास्त्र और भू-राजनीति में बदलाव की संभावनाओं को प्रबल कर दिया है.

व्यंग्य

अनारकली की बगावत...

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

जब से यह सुना गया है कि अनारकली सलीम मियां का घर चौबारा ही नहीं बल्कि उनकी गली भी छोड़ कर डिस्को के लिए चली गई है .तब से यह खबर सुन कर सारा का सारा मोहल्ला सन्न रह गया है. मोहल्ले का एक- एक शोहदा यह जानता था कि एक न एक दिन अनारकली को तो फु...र्र होना ही है. आखिर बेचारी कब तक सहती. हर चीज सहने की एक हद भी होती है .जब यह ना काबिल -ए-बर्दाश्त हो गई तो वो आखिर सलीम मियां की गली छोड़ कर चली ही गई .उसको तो जाना ही था, और वह चली गई. और वह अपने पीछे छोड़ गई जुल्म ओ सितम की एक लंबी दास्तां. जीतने मुंह उतनी बात. लगता है कि अनारकली का उस काले लबादे में दम घुटने लगा होगा. वो ठहरी 21 वीं सदी की लड़की थी. वो टीवी देखती थी, ओटीटी पर फ़िल्में देखती थी. आखिर कब तक अपने जज्बात को दबा कर रखती. उसका भी मन था कि वह घर की चार दिवारी से बाहर निकल कर आसमान की खुली हवा में फाख्ता की तरह परवाज़ भरे. पर ये सलीम मियां को मंजूर नहीं था. खुद तो छैला बने शिकारगाहों में शिकार ढूंढा करते थे और बेचारी अनारकली को पिंजरे वाली मुनिया बना कर कैद कर रखा था.

अनारकली के सलीम की गली को छोड़ कर चली जाने से शहर में हंगामा ही मच गया. जहां देखो वहां एक ही चर्चा थी कि भाई जान अनारकली सलीम भाई की गली छोड़ कर डिस्को चली गई है. हर जुबान पर यही ख़बर थी, भाई जान चली गई .अनारकली चली गई. चौक - चौराहों और नुक्कड़ों पर ये ही हॉट ख़बर थी, कि भाई जान अनारकली चली गई. लोगों की जुबानों को तो छोड़ो, सलीम भाई की गली छोड़ कर चले जाने पर किसी मुएं ने गाना ही बना दिया. भाई जान अपने मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो पनवाड़ी की दुकान पर रेडियो में कोई औरत गाना गा रही थी - अरे छोड़ छाड़ कर अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, चली रे चली.....इतना ही नहीं वह झूमर भी अपने साथ ले जाना भूल गई. सलीम मियां भी बेइंतहा परेशान थे. सोच रहे थे, बतलाओ जिस अनारकली के लिए उन्होंने जिल्ले इलाही से पंगा लिया था .वही अनारकली डिस्को जाने के लिए हम से तो हम से वह हमारी गली से भी रुखसत हो गई. सलीम भाई अपनी रूलाई अपने होठों में रोक कर बोले - अनारकली ये तुमने ठीक नहीं किया. हमने तुम से मोहब्बत की थीअनारकली. सच्ची वाली मोहब्बत. यह मोहब्बत हमने दिल से की थी, किसी सियासी पार्टी की मोहब्बत की दुकान से नहीं खरीदी थी, अनारकली. उनकी दुकान पर तो चाइनीज़ वाली मोहब्बत मिलती है. सलीम मियां पहले से ही जानते थे कि चाइनीज़ चीजों के बारे में तो यह मशहूर है कि चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक. पर अनारकली मेरी मोहब्बत तो पाक मोहब्बत थी. उसके सामने सारे जहां की मोहब्बत ख़ाक थी. इस खबर से पूरे मोहल्ले में खलबली मची हुई थी. ऐसे में तय यह हुआ कि यह पता लगाया जाए कि आख़िर ये ख़बर कैसे और किसने लीक करी. मोहल्ले के नए नए बने एक कॉर्ड होल्डर पत्रकार से संपर्क किया गया. चाय - समोसे और बर्फी के साथ उनका स्वागत सत्कार कर बताया गया कि भाई आपको एक केस सौंप रहे हैं. इन्वेस्टिगेट यह करना है कि अनारकली के सलीम भाई की गली छोड़ कर डिस्को चले जाने की खबर किसने लीक की. पत्रकार महोदय को शोहदों ने चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा गुरू गोल्डन चानिस है. भाई अगर तुमने यह सुराग़ लगा लिया कि अनारकली की ख़बर को लीक करने के पीछे मास्टर माइंड कौन है ? तो गुरू, कसम से पूरी दुनियां जहां में खोजी पत्रकार के रूप में तुम्हारा नाम वैसे ही अमर हो जाएगा जैसे टूली भाई का और करंजिया साहब का नाम दुनिया जहां में चमचमा रहा है.

बस क्या था. हमारे हवा भरने पर पत्रकार महोदय खुद को रूसी करंजिया समझ कर उड़ने लगे . बोले, भाई वो तो ठीक है पर ये बताओ कि इसमें हमारा क्या फायदा. हमने कहा कि गुरू यदि आपने ये ब्रेकिंग न्यूज क्रैक कर ली तो तुम्हारा पूरे मोहल्ले में नाम हो जाएगा. पत्रकार महोदय भी कम घुटी रकम नहीं थे, बोले नाम वाम तो ठीक है कुछ नामा भी होता तो कुछ और बात होती .कुछ नोट वोट दिखाते तो कुछ और बात होती. ये जेब मुस्कुराती तो कुछ और बात होती. हम समझ गए कि गुरू जरूर ये 100,50 की भेंट लिए बिना टस से मस होने वाला नही है, तो भैया उन्हें किसी तरह 'रानी की वाव' वाला नोट भेंट कर काम पर लगाया. क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते तो जो चाय- समोसे और बरफी पर जो इन्वेस्ट किया था वह भी डूब जाता. जैसे टाइटन डूब गया था. हमारे लिए तो चाय - समोसे और बर्फी में किया गया इन्वेस्टमेंट किसी टाइटन के डूबने से कम थोड़े ही है. मन ही मन सोचा दुनिया कितनी खुद गर्ज हो गई है कि एक भी काम फ़ोकट में नहीं करती. कहने को लोग खुद को सोशल वर्कर कहते फिरते हैं. खैर काफ़ी खोज ख़बर के बाद यह सुराग़ लग ही गया कि अनारकली के सलीम भाई की गली छोड़ने वाली ख़बर किसने लीक की. पता चला कि यह खबर अपने बनारसी बाबू समीर भाई ने लीक की है. नहीं समझे न अरे वही समीर भाई अनजान के बेटे. भाई गजब है इन्होंने भी क्या अपने अब्बा हुजूर का क्या नाम रोशन किया है. हाय हाय. उन्होंने ही इस ख़बर को नग़मे में ढाल कर संदीप शाह को दे दिया. साजिद वाजिद ने धुन बना दी. अपने पंजाबी भाई सुखविंदर और ममता शर्मा ने इस को दिलकश आवाज में पिरो दिया और गाना सुनने वालों ने इसे 'हाउस फुल' कर दिया.

यूरेनियम संवर्धन

ऊर्जा के उजाले में छिपा विनाश का अंधकार

ओजस्कर पाण्डेय

यूरेनियम संवर्धन आज की वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु हथियारों की होड़ और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में स्थित एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय है. यह केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन, संप्रभुता, विकास और वैश्विक शांति के बीच संतुलन साधने का माध्यम बन चुका है. जिस तकनीक का उपयोग एक ओर स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है, वही तकनीक दूसरी ओर विनाशकारी परमाणु हथियारों के निर्माण में भी सहायक हो सकती है.

यही द्वंद्व इसे वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विवादास्पद और नियंत्रित क्षेत्रों में से एक बनाता है. यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन और हथियार निर्माण दोनों में होता है. प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्यत: दो आइसोटोप होते हैं—यू-238 और यू-235. इनमें से यू-235 वह आइसोटोप है जो परमाणु विखंडन के लिए उपयुक्त होता है. किंतु प्राकृतिक यूरेनियम में यू-235 की मात्रा केवल लगभग 0.7% होती है, जो ऊर्जा उत्पादन के लिए अपर्याप्त है. इसीलिए यूरेनियम को 'संवर्धित' किया जाता है, अर्थात उसमें यू-235 की मात्रा बढ़ाई जाती है. यही प्रक्रिया यूरेनियम संवर्धन कहलाती है.

संवर्धन का स्तर इस तकनीक के उद्देश्य को निर्धारित करता है. यदि यू-235 की मात्रा 3-5% तक बढ़ाई जाती है, तो यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोगी होता है. वहीं यदि इसे 90% या उससे अधिक तक संवर्धित किया जाए, तो यह परमाणु हथियार बनाने के लिए उपयुक्त बन जाता है. इस प्रकार, एक ही तकनीक ऊर्जा और विनाश दोनों का माध्यम बन सकती है. यही कारण है कि यूरेनियम संवर्धन पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जाती है.

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यूरेनियम संवर्धन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु अप्रसार का है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेषकर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद, दुनिया ने परमाणु हथियारों की भयावहता को देखा. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि परमाणु हथियारों का प्रसार न हो. इसी उद्देश्य से परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई, जिसके तहत केवल पाँच देशों—अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन—को आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र माना गया, जबकि अन्य देशों को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोका गया.

हालांकि, एटीपी के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की अनुमति दी गई है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन की तकनीक पर नियंत्रण रखा गया है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस बात की निगरानी करती है कि कोई देश इस तकनीक का दुरुपयोग न करे. इसके बावजूद, कई देशों ने इस तकनीक को विकसित करने का प्रयास किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न हुआ है. ईरान का उदाहरण इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है. ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को 'शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन' के लिए बताया, लेकिन पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका, को संदेह था कि वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है. इस विवाद ने वर्षों तक वैश्विक कूटनीति को प्रभावित किया और अंतत: 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में एक समझौता हुआ, जिसके तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई. हालांकि बाद में इस समझौते से अमेरिका के हटने के बाद फिर से तनाव बढ़ गया. उत्तर कोरिया का मामला और भी जटिल है. उसने खुले तौर पर परमाणु हथियारों का परीक्षण किया और यूरेनियम संवर्धन को अपनी सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया.

> अंतत:, यूरेनियम संवर्धन केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता के सामने एक नैतिक और रणनीतिक चुनौती है. यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम तकनीकी प्रगति का उपयोग किस दिशा में करना चाहते हैं—विकास और शांति के लिए या विनाश और संघर्ष के लिए. सही दिशा का चुनाव ही यह तय करेगा कि यह तकनीक मानवता के लिए वरदान साबित होगी या अभिशाप. आज, जब दुनिया एक नए ऊर्जा युग के द्वार पर खड़ी है, यह निर्णय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है. यूरेनियम संवर्धन का भविष्य केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि वैश्विक नीतियों, कूटनीति और मानव मूल्यों में तय होगा. यदि सही संतुलन बनाया गया, तो यह तकनीक मानवता के लिए वरदान साबित हो सकती है; लेकिन यदि संतुलन बिगड़ा, तो यही तकनीक हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है.

पश्चिम बंगाल का अद्वितीय चुनाव : याद रहेगा

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

29 अप्रैल 2026 को संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कई दृष्टियों से अनेक मामलों में अभूतपूर्व व कल्पनातीत होकर ऐतिहासिक हो गया है.

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के अधीन विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए मतदाता सूची संबंधी प्रक्रिया को स्वयं के नियंत्रण में लेना एक नई अद्भुत मिसाल है.दुर्भाग्यवश उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जोयमाल्या बागची की यह टिप्पणी बहुत ही वेदना पूर्ण तथा अभी तक की संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था के विरुद्ध है, जब उन्होंने व्यावहारिक रूप से कहा कि एक चुनाव चक्र में इतने मतदाताओं का वंचित रहना पहाड़ नहीं तोड़ेगा.

न्यायपालिका ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारियों (लगभग 700 पश्चिम बंगाल, झारखंड व उड़ीसा से) को इस प्रक्रिया में शामिल किया, जिसे स्वयं

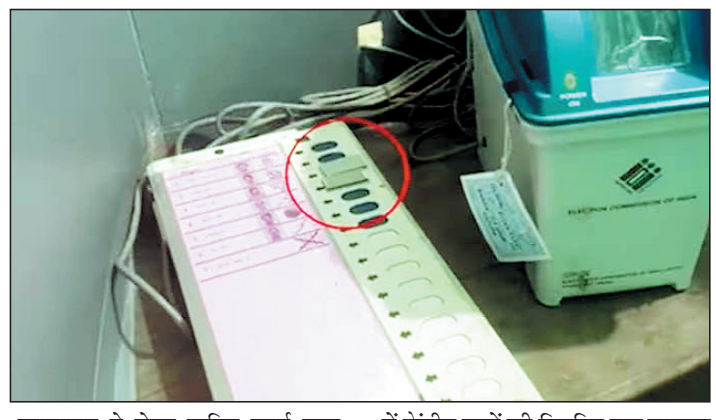

न्यायालय ने बेहद कठिन कार्य कहा. आम चुनावों के पूर्व, समय पर नई संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की एकमात्र जिम्मेदारी, चुनाव आयोग की ही है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि यदि प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी, तो क्या पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराना एक विकल्प हो सकता था? (बिना एसआईआर किए) ठीक उसी प्रकार जिस सूची पर 2024 के लोकसभा चुनाव कराये गए थे. बंगाल के साथ हुए असम के चुनाव 'एसआईआर' किए बिना कराये गये. पश्चिम बंगाल में लगभग 2.4 लाख केंद्रीय बलों की तैनाती ने भी इस चुनाव को विशिष्ट व अति संवेदनशील बना दिया. राज्यों के चुनावों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया हैं. परन्तु अभूतपूर्व स्तर पर केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों आरपीएफ, बीएसएफ, आईटी बीपी एवं एसएसबी की नियुक्तियां बंगाल में 294 सीटों के लिए लगभग 2.40 लाख की गई. यह संख्या वर्ष 2024 के पूरे 543 लोकसभा सीटों जिसमें 4131 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र शामिल है, के चुनाव में सम्पूर्ण देश में जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, की गई 3.40 लाख नियुक्ति से मात्र एक लाख ही कम है. बंगाल में पिछले चुनाव में लगभग 80 हजार सैनिकों की नियुक्तियां ही की गई थी.

देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि दो मतदाता दिशारअली मोंडल एवं गणेश मजूमदार को लुंगी पहनकर वोट डालने से रोका गया और अंतत: उन्हें अपनी ड्रेस पहन कर आने पर वोट डालने दिया गया. लुंगी तो तमिलनाडु की ड्रेस कोड ही है, जहां बंगाल के साथ ही अभी चुनाव संपन्न हुए हैं. दिगंबर जैन मुनि को मताधिकार है कि नहीं? पर यह सवाल उठता है कि क्या मतदान जैसे संवैधानिक अधिकार पर किसी प्रकार के 'अनौपचारिक मानदंड' लागू किए जा सकते हैं?

पांचों राज्यों के चुनाव में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भाजपा को हर हाल में फायदा होगा. चाहे सीटों की संख्या की बात हो या मतों की संख्या, भाजपा केरलम व तमिलनाडु जहां विपक्ष में है, वहां पर भी उसका आधार निश्चित रूप से परिणाम आने पर बढ़ा हुआ मिलेगा. भाजपा की इस बात के लिए प्रशंसा की ही जानी चाहिए कि एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर जहां विपक्ष शासित राज्य प्राय: नहीं झेल पाते है, सरकार पलट जाती हैं, वहीं भाजपा को सफलतापूर्वक सामना करने में महारत हासिल है. गुजरात व मध्य प्रदेश इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं.

बंगाल चुनाव परिणाम को आप दो उदाहरण से समझिए! अटल बिहारी ने कहा करते था, रोटियां पलटिये, नहीं तो जल जायेगी. क्या ऐसे होने जा रहा है? मतलब पिछले चुनाव की अस्वस्थ ममता (पैर पर प्लास्टर चढ़ा था) की तुलना में वर्तमान स्वस्थ ममता कमजोर सिद्ध हो जाएगी? अथवा ममता भी भाजपा की एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर की तकनीक को सफलतापूर्वक अपना रही है? मेरा स्पष्ट मत है कि इन पांचों राज्य के चुनाव में केरलम जहां सरकार बदल रही है, बाकि सरकारें रिपीट (पुनरावृत्ति) हो रही हैं. बंगाल में रिपीट होने का प्रमुख कारण 27% मुसलमान वोट और महिला वोटो में ममता का आगे होना है. यह आशंका/आशा भी निर्मूल है कि ममता नहीं अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगे. जरूर यह परिस्थितियों वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव के समय बन सकती हैं.

अद्भुत संयोग: देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्ष 2014 से 14 बार मतदान के दिन मंदिरों में गए, जिसमें 80 प्रतिशत जीत हुई. बंगाल के हुए चुनाव में मोदी 23 अप्रैल के मतदान के दिन ''बेलूर मठ'' और 29 अप्रैल को ''काशी विश्वनाथ मंदिर'' में. क्या यहां भी इतिहास दोहराया जाएगा? ''मां माटी मानुष'' से आगे बढ़कर ममता का नया नारा बदला नोय, बदलाव चाई'? 'बदलाव नोय, बदला चाई' (परिवर्तन नहीं, बदला चाहिए) क्या धरातल पर उतरेगा? उत्तर 4 मई को मिलेगा.